बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 239

समझदारी भरा कदम

देश की तमाम दूरसंचार कंपनियों ने दिसंबर से मोबाइल फोन शुल्क दर में बढ़ोतरी की घोषणा करके परिपक्वता दिखाई है। हालांकि अभी यह पता नहीं कि कितनी बढ़ोतरी की जाएगी लेकिन बीते करीब एक दशक में पहली बार हो रही शुल्क वृद्धि, भारी घाटे और ऋण के बोझ से दबे इस क्षेत्र में बदलाव का अहम मोड़ साबित हो सकती है। इस क्षेत्र की खस्ता हालत के लिए काफी हद तक औंधे मुंह गिरी कीमतें भी उत्तरदायी हैं और कीमतों में यह गिरावट गलत प्रतिस्पर्धा के कारण आई। यह कदम दूरसंचार क्षेत्र को दोबारा पटरी पर लाने की दिशा में पहला कदम साबित हो सकता है। हालांकि काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि शुल्क दरों में बदलाव का ग्राहकों पर क्या असर होता है।

फिलहाल माना जा रहा है कि दूरसंचार कंपनियों की इस शुल्क वृद्धि से सेवाओं के मूल्य में 15 से 30 फीसदी तक इजाफा हो सकता है, हालांकि उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर थोड़े ही संशोधन किए जाएंगे। अतीत में कंपनियों का कहना था कि उनका राजस्व या प्रति उपभोक्ता औसत राजस्व उनके लिए कुल कारोबार से अधिक अहम था। परंतु प्रतिस्पर्धी बाजार में वे उपभोक्ताओं की तादाद बढ़ाने के दबाव से मुक्त नहीं हो पाईं। ऐसे में एक नकदी संपन्न कंपनी के आगमन ने बाजार को उलटपुलट कर दिया। चूंकि उसी मोबाइल नंबर को आसानी से दूसरी कंपनी में पोर्ट किया जा सकता है इसलिए दूरसंचार कंपनियां दरों में बदलाव करते हुए सावधानी बरतेंगी।

बढ़े हुए शुल्क से इस उद्योग में एकरूपता आएगी जबकि यह खस्ता वित्तीय हालत के बावजूद पिछले काफी समय से दरों में कमी करने की होड़ में है। ऐसे में इसे तत्काल बदलाव लाने के लिए सरकार से राहत की आवश्यकता होगी। सरकार ने अतीत की स्पेक्ट्रम नीलामी के बकाया भुगतान के लिए दूरसंचार कंपनियों को दो वर्ष का समय दिया है। इससे भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो जैसी तीन बड़ी निजी कंपनियों को करीब 42,000 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। हालांकि बाद के वर्षों में इस राशि पर ब्याज लगेगा और कंपनियों का कुल भुगतान बढ़ेगा। परंतु नकदी चुकाने में जो तात्कालिक राहत मिलेगी उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। खासकर भारती एयरटेल और वोडाफोन के मामले में जिनका शुद्ध घाटा दूसरी तिमाही में करीब 74,000 करोड़ रुपये रहा। इससे यह जोखिम उत्पन्न हो गया था कि सरकारी राहत के बिना वे चलती भी रह सकेंगी या नहीं।

इस लिहाज से देखें तो दो वर्ष की यह अवधि दूरसंचार कंपनियों की नकदी की समस्या का कोई दूरगामी हल नहीं होगा। इस मोड़ पर यह स्पष्ट नहीं है कि विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाओं पर सरकार तनावग्रस्त दूरसंचार उद्योग को आगे और राहत मुहैया कराएगी या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समायोजित सकल राजस्व की सरकार की परिभाषा को बहाल रखने के बाद इस क्षेत्र को करीब 1.4 लाख करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता है। उद्योग जगत के अनुमान के अनुसार सरकार को कंपनियों का शुल्क तार्किक बनाना चाहिए। ऐसा करने से इस क्षेत्र की वित्तीय सेहत दुरुस्त करने में मदद मिलेगी।

दूरसंचार कंपनियां लंबे समय से बकाया समायोजित सकल राजस्व के लिए प्रावधान नहीं कर पाईं और इस क्षेत्र का बहीखाता रिकॉर्ड स्तर पर लुढ़क गया। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत कई सेवा प्रदाताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दाखिल की है। उन्होंने जुर्माने और ब्याज की माफी चाही है। निष्कर्ष के परे सरकार और सेवा प्रदाताओं दोनों को ऐसे तरीके तलाशने की आवश्यकता है जो इस क्षेत्र को मजबूत बना सकें क्योंकि इस क्षेत्र के विकास का देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर होगा।

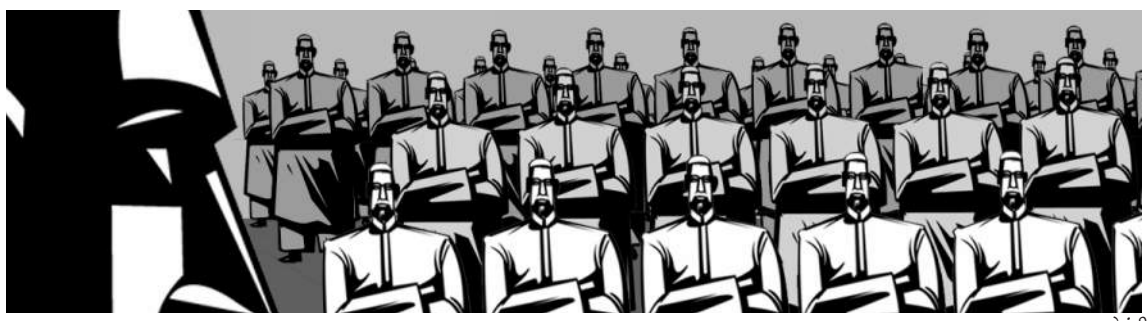

अजय मोहंती

क्या भारतीय मुस्लिम मायने रखते हैं?

भारतीय मुस्लिमों को मतदान में अपनी पंसद के लिए दंडित किया जा रहा है और सत्ता में उनका उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की यह स्थायी शिकायत रही है कि देश की राजनीति में मुस्लिमों को उनकी हैसियत से अधिक भाव मिलता रहा है। भाजपा के नेता और उसके बड़े बौद्धिक तथा एक्सप्रेस समूह में मेरे सहकर्मी रह चुके बलबीर पुंज ने एक बातचीत में मुझसे कहा था, 'भारत पर कौन राज करेगा और कौन नहीं यह तय करने का अधिकार मुस्लिमों के पास है?'

यह बातचीत तब हुई थी जब सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी राजग सरकार लोकसभा में एक वोट से गिर गई थी क्योंकि तमाम 'धर्मनिरपेक्ष' दल उसके खिलाफ एकजुट हो गए थे। इससे पहले सन 1996 में वाजपेयी की पहली राजग सरकार मात्र 13 दिन में गिर गई थी।

राजग की दूसरी सरकार एक वर्ष से कुछ अधिक समय तक चली और पुंज की दलील थी कि जिन दलों को मुस्लिम वोट मिलने में रुचि थी या उन्हें गंवा देने का डर था वे भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए कुछ भी कर सकते थे। पुंज को लगता था कि मुस्लिम मत और धर्म निरपेक्ष मूल्यों के प्रति उन दलों की प्रतिबद्धता महज दिखावा थी। मुझे लगता है कि संप्रग-1 की सरकार के बाद इस धारणा में और अधिक मजबूती आई होगी जब भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए वाम दलों ने भी कांग्रेस का समर्थन किया था। उस वक्त कांग्रेस और भाजपा की सीटों में मामूली अंतर था। कांग्रेस को 145 और भाजपा को 138 सीट मिली थीं।

भाजपा ने कई बार मुस्लिमों से करीबी बढ़ाने का प्रयास किया। अल्पसंख्यकों की दृष्टि से देखें तो वाजपेयी स्वयं पार्टी का सबसे समावेशी और सौहार्दपूर्ण चेहरा थे। लालकृष्ण आडवाणी ने कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों को आगे बढ़ाया, यहां तक कि मुस्लिम वाम को भी। वह मुस्लिमों के त्योहारों में शामिल हुए और जिन्ना की तारीफ तक की। एपीजे अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति तक बनाया गया। वाजपेयी और आडवाणी की भाजपा का पूरा प्रयास मुस्लिम मतों में सेंध लगाने का था। परंतु पार्टी इसमें नाकाम रही।

भाजपा ने इसका अर्थ यह लगाया कि मुस्लिम ही यह तय करेंगे कि भारत पर कौन राज करेगा। संप्रग के एक दशक के शासन के दौरान जब देश भर में भाजपा सत्ता से वंचित रही तब यह धारणा मजबूत रही। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उदय हुआ और उन्होंने पूरा गणित बदल दिया। उन्होंने बिना मुस्लिम मतदाताओं की सहायता के बहुमत हासिल किया। देश की राजनीति में यह एक नया युग था। भाजपा के कई नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया। उनका कहना था, 'हमने अब मान लिया है कि हमें मुस्लिमों और ईसाइयों को छोड़कर केवल 80 फीसदी मतदाताओं के साथ मैदान में उतरना है।' एक बार इस हकीकत को स्वीकार करने के बाद चुनौती आसान थी: हिंदू वोटों का 50 फीसदी हासिल कर वे आसानी से शासन कर सकते थे। 2019 में उन्होंने इसे साबित किया। भारतीय राजनीति का सबसे अप्रत्याशित बदलाव आ चुका था और करीब 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक बना दी गई थी। इन बातों में यकीन करने की आवश्यकता नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक के कारण मोदी का अहसान माना या आकांक्षी युवा मुस्लिमों ने भाजपा को वोट दिया। हर विश्वसनीय एक्जिट पोल का जनांकीय विश्लेषण उपरोक्त बातों को साबित करता है। इससे भाजपा के धर्मनिरपेक्ष प्रतिद्वंद्वी स्तब्ध रह गए। मुस्लिम भी जवाब तलाशने में लग गए। खुद को 20 करोड़ मुस्लिमों की जगह रखकर देखिए तो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आएगी: मेरे मत की ताकत समाप्त हो चुकी है, ठीक है लेकिन क्या मुझे सत्ता में मेरी वाजिब जगह भी नहीं मिलनी चाहिए?

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

मोदी सरकार का यह छठा वर्ष है और उसमें केवल एक मुस्लिम मंत्री हैं मुख्तार अब्बासी नकवी। उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का प्रभारी बनाया गया है। यह इतिहास के उन अस्वाभाविक पलों में से एक है जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सशस्त्र बलों के प्रमुख, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों, निर्वाचन आयोग या न्यायपालिका में किसी अहम पद पर कोई मुस्लिम नहीं है। देश के किसी राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। जम्मू कश्मीर में जहां ऐसा हो सकता था, वह अब राज्य ही नहीं रहा। देश के किसी प्रमुख मंत्रालय में कोई मुस्लिम सचिव नहीं है। कोई महत्त्वपूर्ण नियामक भी मुस्लिम नहीं है। सरसरी तौर पर याद करें तो हामिद अंसारी के अलावा सन 2015 से 2017 तक देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे नसीम जैदी आखिरी मुस्लिम थे जो किसी संवैधानिक पद पर रहे। देश के 37 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में केवल दो मुस्लिम राज्यपाल हैं: नजमा हेपतुल्ला और आरिफ मोहम्मद खान।

भाजपा की सबका साथ, सबका विकास की दलील से हम सभी परिचित हैं। उसकी अगली दलील है देश में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा न होना। इसके बाद अन्य बातें हैं। मसलन जैसा कि द प्रिंट में सान्या धींगड़ा और फातिमा खान की रिपोर्ट में बताया गया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में आईएएस जैसी परीक्षा में मुस्लिम प्रत्याशियों की सफलता की दर में मामूली सुधार हुआ है। इसके अलावा संप्रग की तुलना में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियां मुस्लिम छात्रों को अधिक मिली हैं। परंतु एक समानतापूर्ण व्यवस्था में देश की 15 फीसदी आबादी सत्ता और शासन में अपना वाजिब हक चाहेगी। हम आपको बताते हैं सन 2014 के बाद से इस सवाल का भाजपा क्या जवाब देती है: 'आप हमारे खिलाफ एकजुट होकर मतदान नहीं कर सकते और यदि आप हमारे शत्रु हैं तो आप सत्ता में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकते।'

इस आलेख का जो शीर्षक हमने दिया है, उसका अर्थ यही रेखांकित करना है कि संवैधानिक समता की भावना को कितना क्षीण कर दिया गया है। आपको मतदान का अधिकार है, आप छात्रवृत्तियां लीजिए, नौकरियों और अन्य अवसरों का लाभ लीजिए लेकिन सत्ता में भागीदारी चाहिए तो सोच समझकर मतदान कीजिए। यह कितनी बुरी बात है कि देश की 15 फीसदी आबादी इतनी बिखरी हुई है कि लोकसभा में इसके केवल 27 सांसद हैं। यह मॉडल आपने कहीं और देखा होगा। इजरायल की विशाल मुस्लिम आबादी दुनिया की इकलौती अरब आबादी है जिसे मुक्त और स्वतंत्र मताधिकार, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक अवसर उपलब्ध हैं। परंतु वहां भी राजनीतिक और सत्ता के ढांचे में उनकी पहुंच सीमित है। इजरायल एक गणतंत्र है लेकिन यहूदी गणतंत्र। भारत में भी मुस्लिमों के साथ ऐसा ही व्यवहार हो रहा है। फर्क केवल यह है कि भारत को कभी हिंदू गणराज्य के रूप में नहीं देखा गया, न सोचा गया। यहां आकर पूरी दलील नाकाम हो जाती है।

भारतीय मुस्लिम या भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम कोई अखंड इकाई नहीं हैं। जरा सोचिए, दुनिया के कुल मुस्लिमों के 40 फीसदी उपमहाद्वीप में रहते हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र के मुस्लिमों में से आईएसआईएस में शामिल होने वालों की तादाद कभी कुछ सौ से आगे नहीं गई। इसमें भी भारतीयों की तादाद तो सौ तक भी नहीं पहुंची। क्यों?

इसलिए क्योंकि उपमहाद्वीप के मुस्लिमों में भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश के रूप में अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना भरी पड़ी है। उनके पास अपना ध्वज है, राष्ट्रगान है, क्रिकेट टीम है और अपने नेता हैं जिनसे वे प्यार और नफरत कर सकते हैं। मिथकीय इस्लामिक गणराज्य और खलीफा की अवधारणा उन्हें नहीं लुभाती। उपमहाद्वीप के अलग-अलग हिस्सों में मुस्लिम अपनी पहचान, भाषा, जातीयता, संस्कृति और राजनीतिक विचारधारा के आधार पर बंटबंटे हुए हैं। बांग्लादेश तभी अस्तित्व में आया जब सांस्कृतिक और भाषाई पहचान धार्मिक आधार पर बने द्विराष्ट्र पर भारी पड़ गई।

यह इस क्षेत्र की ताकत है और तकरीबन पूरे भारत पर यह लागू होती है। देश में वर्ष 2014 के बाद अप्रासंगिक बना दिए गए मुस्लिमों को यूं अलग थलग महसूस करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। उनकी खामोशी को सहमति मानने की भूल नहीं की जानी चाहिए। भारतीय मुस्लिमों में एक नया मध्य वर्ग उभर आया है। एक शिक्षित और पेशेवर वर्ग भी उभरा है। वह पुराने वामपंथी उर्दू भाषी वर्ग या उलेमाओं को अपना नेता नहीं मानता। जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्वान आसिम अली ने लिखा, अब यह वर्ग कड़े सवाल कर रहा है, आप उनकी मत देने की प्राथमिकता के लिए दंडित कर अपना प्रतिशोध ले सकते हैं लेकिन यह आत्मघाती होगा। कोई देश या समाज अपनी आबादी के छठे हिस्से को हाशिये पर रखकर न तो समृद्ध हो सकता है और न सुरक्षित।

सिनेमा और स्ट्रीमिंग वीडियो कारोबार की तुलना

नेटफ्लिक्स की पुरस्कृत ओरिजिनल सीरीज द क्राउन का तीसरा सीजन जारी कर दिया गया है। इस सीजन में ओलिविया कोलमैन ने क्वीन इलिजाबेथ द्वितीय के उस किरदार को बखूबी अपनाया है जिसे शुरुआती दो सीजन में क्लेयर फोय ने निभाया था।

यूनाइटेड किंगडम की महारानी का सफर युवा इलिजाबेथ से शुरू होता है जो अपने प्रेमी से विवाह के मामले में अडिग रहीं लेकिन महारानी बनने के बाद शुरुआती कुछ अवसरों पर ही लड़खड़ा गईं। उन्होंने विंस्टन चर्चिल जैसे प्रधानमंत्रियों से निपटना सीखा या स्वेज संकट से निपटीं लेकिन महारानी बनने के कारण उनके विवाह और अपनी बहन के साथ उनके रिश्तों पर गंभीर असर हुआ। सीरीज बताती है कि क्राउन या ताज सबसे पहले आता है, भले ही उनकी व्यक्तिगत मान्यता चाहे जो भी हो।

द क्राउन सीरीज न केवल देखने में अच्छी है बल्कि बौद्धिक दृष्टि से भी वह एक शानदार सीरीज है। यह इतिहास का एक सबक तो देती ही है, साथ ही यह मानव स्वभाव और सबसे महत्त्वपूर्ण फिल्म निर्माण के बारे में जानकारी भी देती है। 10 कड़ियों वाले हर सीजन के निर्माण के करीब दो वर्ष का समय लगा। शोधकार्य, लेखन, सेट, निर्माण की गुणवत्ता और प्रदर्शन आदि के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि इसे बड़े पर्दे पर भी जारी किया जा सके। यहां मैं उस मुद्दे पर आती हूं जिसने यह स्तंभ लिखने की प्रेरणा दी। फिल्मों का ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म के हिसाब से रचनात्मक और वाणिज्यिक निर्माण उचित है लेकिन फिल्मों की तरह इनके दायरे की व्यापकता एक बड़ा मुद्दा है।

रचनात्मक पहलू की बात करें तो वीडियो स्ट्रीमिंग की सामग्री और विषयवस्तु की मांग दुनिया भर में बढ़ी है। सिंगापुर की सलाहकार सेवा मीडिया पार्टनर्स एशिया के मुताबिक भारत में 2016 जो मूल सामग्री बमुश्किल 20 घंटे की थी वह 2018 में 10 शीर्ष ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 400 घंटे तक पहुंच गई। एक अनुमान है कि

मीडिया मंत्र

वनिता कोहली-खांडेकर

वर्ष 2019 के आखिर तक 1,000 घंटे की ताजा विषयवस्तु उपलब्ध हो सकती है। यह सामग्री 300 से 500 नई फिल्मों या 50 करोड़ डॉलर मूल्य के फिल्म की गुणवत्ता वाली सामग्री के बराबर होगी।

करीब 1,600 फिल्मों के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है परंतु इसमें 500 और उच्च गुणवत्ता वाली फिल्मों को शामिल करना आसान नहीं है। भारत में नेटफ्लिक्स के अंतरराष्ट्रीय ओरिजिनल्स के पोस्ट प्रोडक्शन निदेशक विजय वेंकटरमणन कहते हैं कि हम भारतीय फिल्में तो अच्छी बनाते हैं लेकिन एक फिल्म बनाने में साल भर लग जाते हैं। जबकि ओटीटी पर एक वर्ष में छह सीरीज बनानी होती हैं। अपालस एंटरटेनमेंट के छह शो ऑनलाइन चल रहे हैं जबकि कई अन्य अभी निर्माण की प्रक्रिया में हैं।

कंपनी के सीईओ समीर नायर कहते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस जैसे शो बनाने में एक से दो वर्ष का वक्त लगता है। समय बीतने के साथ यह अवधि कम होकर 15 महीने हो गई है और नायर कहते हैं कि यदि लेखन और निर्माण की गुणवत्ता को बनाए रखना है तो इसे 12 महीने से कम नहीं करना चाहिए।

जरूरत इस बात की है कि प्रतिभा और कौशल दोनों का विस्तार किया जाए, वह भी बिना रचनात्मकता या देश के रचनात्मक उद्योग की मजबूती गंवाए। संयोग देखिए कि इस वर्ष तीन भारतीय वेब सीरीज सैक्रेड गेम्स 1, लस्ट स्टोरीज और द रीमिक्स को अंतरराष्ट्रीय एम्मी अवार्ड के लिए नामित किया गया है।

इस वर्ष अक्टूबर में नेटफ्लिक्स ने एम्सटर्डम के एपोस्टलैब के साथ मिलकर मुंबई में चार दिवसीय पोस्ट प्रोडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में विजुअल और स्पेशल इफेक्ट के साथ, ध्वनि, संगीत आदि तमाम विषयों पर चर्चा के सत्र आयोजित किए गए थे। 30 से अधिक पेशेवरों ने इसमें हिस्सा लिया लेकिन यदि भारत के 1.2 अरब डॉलर के फिल्म उद्योग को व्यापक सामग्री बनाने लायक बनाना है तो ऐसे दर्जनों प्रयास करने होंगे।

वाणिज्यिक पक्ष को देखें तो इस वर्ष वीडियो स्ट्रीमिंग से जो 8,000 करोड़ रुपये का राजस्व अनुमानित है उसका दोतिहाई विज्ञापन से आएगा। बहरहाल शेष एक तिहाई राशि ग्राहकों द्वारा लिए जाने वाले सबस्क्रिप्शन से आती है और ओरजिनल्स की फंडिंग और मार्जिन उसी से बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रति हजार दर्शकों के आधार पर विज्ञापन दर बहुत कम है। इस महीने डिज्नी प्लस की लॉचिंग को लेकर काफी उत्साह रहा लेकिन मेरा मानना है कि नेटफ्लिक्स जैसे निष्पक्ष मंच स्ट्रीमिंग का फायदा उठाने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में हैं। यूट्यूब, हॉटस्टार या जी5 से इतर नेटफ्लिक्स के पास न तो किसी तरह की सब्सिडी है और न ही उसके पास बचाने के लिए कोई मौजूदा कारोबार है। यह पूरी तरह बेहतरीन विषयवस्तु के प्रसारण पर निर्भर है। ऐसा होने पर ही लोग अपने सब्सक्रिप्शन का नवीनीकरण कराएंगे।

फिल्मों के साथ इसकी तुलना स्वाभाविक है। फिल्मों को किसी भी तरह की रियायत या विदेशी फिल्मों के आयात से किसी तरह का बचाव हासिल नहीं होता। भारतीय फिल्में बची रहीं और फलीं फूलीं क्योंकि लोग अपनी जेब से पैसे खर्च करके फिल्में देखते हैं। ऐसे में यह खबर सुखद है कि देश में लगभग सभी प्रमुख ओटीटी ब्रांड्स का सबस्क्रिप्शन तेजी से बढ़ रहा है। बल्कि 2018 की तुलना में 2019 में यह दोगुना बढ़ गया।

आशा की जानी चाहिए कि भारतीय ओटीटी आनेवाले दिनों में व्यापक पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण और मुनाफे वाला प्रदर्शन करेंगे।

कानाफूसी

भाजपा और आत्मालोचना

जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर लगने वाले इस आरोप को गलत बताते हैं कि देश को लेकर पार्टी का नजरिया अलोकतांत्रिक है, उनकी दलील में शायद दम है। प्रधानमंत्री कार्यालय में ढेर सारी पत्र-पत्रिकाएं आती हैं ताकि वहां आकर प्रतीक्षा करने वाले आगंतुक व्यस्त रह सकें और अपने समय का सदुपयोग कर सकें। दिलचस्प बात यह है कि इन पत्र-पत्रिकाओं में कमल संदेश और पांचजन्य नजर नहीं आते। इनके स्थान पर चमकदार पन्नों वाली यात्रा और पर्यटन संबंधी पत्रिकाएं और यहां तक कि इकनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली तक नजर आती है। इस पत्रिका के इस अंक की आवरण कथा में ही लिखा है, 'क्या अमेरिकी नेतृत्व के साथ व्यक्तिगत रिश्ते का इस्तेमाल भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करने के लिए किया जा सकता है? ऐतिहासिक रूप से अगर हम इस संबंध में किए गए गलत आकलन को ध्यान में रखें तो यह अपने आप में चिंता का विषय है।' जाहिर सी बात है कि यह सब देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी की यह कहते हुए आलोचना नहीं की जा सकती है कि पार्टी अपनी आलोचना पसंद नहीं करती है।

आपका पक्ष

देश में 13 लाख घर अब भी अंधेरे में

महानगरों, शहरों, कस्बों तथा गांवों को जहां बिजली रोशन कर रही है, वहीं यह देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी लाखों घरों में बिजली नहीं पहुंच पाई है। घरों में बिजली नहीं पहुंच पाने में सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश की है। संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि अभी तक देश में 13 लाख 90 हजार 375 घरों में बिजली कनेक्शन नहीं लग पाया है। इनमें कुछ संख्या ऐसे लोगों की है जो बिजली कनेक्शन नहीं लगवाना चाहते थे। फिर भी देश में 13 लाख घरों में बिजली कनेक्शन नहीं होना सरकार की उदासीनता को दर्शाती है। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने घरों में बिजली कनेक्शन नहीं लगवाना चाहता हो। अलग-अलग राज्यों में बिजली दर अलग-अलग होती है। इसके अलावा कनेक्शन चार्ज और जमा राशि भी अलग-अलग होती है। सबसे बड़ी बात बिजली कनेक्शन लेने में दस्तावेज प्रक्रिया भी परेशानी वाली होती है।

कोई एक दस्तावेज नहीं मिला तो कनेक्शन नहीं लग पाता है। इस सरकारी पेच को देखते हुए कई लोग शायद कनेक्शन नहीं लगवाना चाहते हों। दूसरी सबसे बड़ी बात कटिया लगा कर बिजली लेने की है। कई जगहों पर लोग कटिया लगा कर बिजली लेते हैं और जब जांच होती है तो कटिया हटा देते हैं। अगर इन

देश में अभी भी लाखों घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं लग पाया है

सभी खामियों को खत्म कर दिया जाए तो लोग बिजली कनेक्शन क्यों नहीं लेंगे। केंद्र सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। इस योजना के तहत गांवों में बिजली तो पहुंच गई थी लेकिन घरों में कनेक्शन लगने का कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा था। बहरहाल देश के सभी घरों में बिजली पहुंचाना सरकार की पहली जिम्मेदारी है भले ही वह व्यक्ति बिजली कनेक्शन ले या न ले।

रंजीत सिंह, नोएडा

पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं बढ़े

देश में पर्यटन उद्योग काफी बड़ा रूप ले चुका है और देश के विभिन्न जगहों में यह काफी फल-फूल भी रहा है। यहां देश-विदेश से सैलानी घूमने आते हैं जिसके मुताबिक सेवाएं दी जाती हैं। लेकिन आज भी कई पर्यटन स्थलों पर माताओं के लिए अलग कमरा नहीं दिखता है जहां वे अपने शिशु को स्तनपान करा सकें। पर्यटन स्थल जाने वालों में काफी संख्या में परिवार ही जाते हैं और ऐसे कई परिवार में छोटा बच्चा भी रहता है। उन जगहों पर माताएं अपने शिशु को स्तनपान कराने के लिए एकांत जगह खोजती हैं और यह उनके लिए एक परेशानी का सबब होता है। सरकार ने हाल में घोषणा की है कि सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अब बच्चों के साथ आने वाली माताओं के लिए विशेष कमरे की व्यवस्था करना अनिवार्य किया जाएगा। सरकार ने कहा कि विशेष कमरे में शौचालय के साथ माताओं की सहायता के लिए अन्य सुविधाएं भी मौजूद होंगी। यह सरकार की अच्छी पहल है लेकिन इस तरह की सुविधाएं प्रमुख पर्यटन स्थलों के साथ-साथ सभी छोटे बड़े पर्यटन स्थलों में लागू किए जाने की जरूरत है। आज भी कई पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं की कमी देखी जा सकती है। हर पर्यटन स्थलों में सबसे अधिक बिकने वाला पदार्थ पानी की बोतल है। सरकार को सभी पर्यटन स्थलों पर आरओ पानी का प्लांट लगाना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़े।

दिव्या कुमारी, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।